

चिंतन

संसद चलेगी, तभी कोई अपनी बात रख सकेगा

सद नहीं चलने देने से किसी का भला नहीं होगा। संसद चलेगी, तभी विषय भी अपनी बात रख सकेगा। हाल के वर्षों में संसद राप करना एक ट्रैड बन गया है, जो दर्भायर्पूण है पहले भाजपा विषय में थी तो संसद में व्यवधान पैदा करती थी, अब कांग्रेस समेत अनेक दल विषय के लिए तो वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं। इनमा, नरेबाजी, शेरागुल, हूटिंग, नहीं बोलने देना आदि संसद में सांसद के क्रृत्य बन गए हैं। हार बार सत्र शुरू होने से पहले सरकार विषय के साथ संवर्द्धन वैठक करती है, विषय के लिए दो संसदों की अपील करती है, विषय भी सार्थक संसद सत्र का आश्वासन देता है और अनाजे दिन जब सत्र शुरू होता है, विषय संसद को राप कर देता है। दो इस सबसे उब चुका है। विषय जिन मुद्दों पर बहस या बायान की मांग कर संसद में होंगा करता है, या संसद नहीं चलने देता है, अगर उन मुद्दों पर सत्र में वह सदन में बहस चाहता है तो वह तभी सभव है, जब संसद चले। उपराष्ट्रपति जारीपत्र धनखड़ ने कहा है कि 'लोकतंत्र के मंदिरों में व्यवधान और हांगामे के राजनीतिक रूपांतर' के तौर पर हाथियार नहीं बनाया जा सकता।' केवल होंगा माचना कहीं से भी संसद या लोकतंत्र का अनुपान नहीं है। मणिपुर की अपील वैठक बनना ने निश्चित रूप से देश को शर्मसार किया है, इस पर विषय की हार पाया रखना है कि संसद में वह यह तभी ही पाया, जब संसद सुचारू रूप से चलेगी। संसद सत्र आहूत होने के बाद हर दिन करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, ऐसे में संसदों का दायित्व है कि वह संसद के संचालन में सहयोग करें, केवल पार्टी पार्लिमेंट के लिए संसद सत्र को बेकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि संसद के सुचारू व नियमित संचालन के लिए कुछ कठोर नियम बनाएं, जो लागे कि भारत की 21वीं सदी की संसद है। सत्ता पक्ष को भी भवित्व व लचीला रुख अपनाना चाहिए और विषय की मांगों के प्रति उदार रखेंगा रखना चाहिए। विषय की मांगों को खिजकर करने की प्रवृत्ति भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संसद जन प्रतिनिधि हैं, इस नाते वे सर्वेधार्मिक रूप से संसद के प्रति बंधे हुए हैं। संसद से लोकतंत्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। संसद सत्र विधेयक करने, राष्ट्रीय मुद्दों पर विषय करने, नया कानून बनाने आदि के लिए आहूत होते हैं, लेकिन इसे होंगा वा नरेबाजी का मच बना देने से इसकी उपयोगता व्यर्थ हो जाती है। 2014 से अब तक कांग्रेस ने शायद ही किसी संसद सत्र को मुचारू चलने दिया है। सरकार की अपील पर विषय को गैर करना चाहिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा है कि 'लोकतंत्र जनता की भलाई के लिए संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और बहस को कहा जाता है, इस पर भी विषय की मांगों के प्रति उदार रखेंगा रखना चाहिए।' अभी जबकि देश मणिपुर की लोकतंत्र घटना से आक्रोशित है, वहाँ हिंसा व उत्तरदाव की लेकर अफवाह व फज्जी खबरों या फेक वायरल वीडियो आदि से फिर से हिंसा भड़कने का खतरा विद्यमान है, तो ऐसे में इस संदर्भशील मुद्दों पर राजनीति करना कहीं उचित नहीं है। मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल की घटना भी शर्मनाक है। महिलाओं के उत्तीर्ण पर चाहे राजनीति भाजपा करे या कांग्रेस, दोनों गलत हैं। सियासत के लिए देश को नकारत, हिंसा आदि की आग में झोका निकृष्ट कर्त्त्य है। सबकी कोशश मणिपुर में व्याशीशी शांति बहाली की होनी चाहिए। सभी दल संसद चलने दें।



विलेषण

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बहुआयामी गरीबी लोगों की हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 के 24.85 फीसदी से घटकर वर्ष 2019-21 में 14.96 फीसदी हो गई है। यह सूचकांक आय गरीबी के आकलन की गणना परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जारीपाई द्वारा गरीबी के लिए लोगों का सुकूनदेह परिदृश्य 2030 के लिए तय की गई मियाद से बहुत पहले बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करने में मदद मिली। यह गणना लोगों के लिए लोगों की संख्या 2019-21 में 11.5 फीसदी हो गई है। यह सूचकांक आय गरीबी के आकलन की पूरी की व्यवधान के लिए लोगों का अनुपान है। इसके सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुरूप है। इसके तरह पोषण, बाल एवं किसान मुख्य रूप से लोगों को व्यवसाय द्वारा जारीपाई किया जाता है। इस पर विषय की हार पाया रखना है कि संसद में वह यह तभी ही पाया, जब संसद सुचारू रूप से चलेगी। संसद सत्र आहूत होने के बाद हर दिन करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, ऐसे में संसदों का दायित्व है कि वह संसद के संचालन में सहयोग करें, केवल पार्टी पार्लिमेंट के लिए संसद सत्र को बेकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि संसद के सुचारू व नियमित संचालन के लिए कुछ कठोर नियम बनाएं, जो लागे कि भारत की 21वीं सदी की संसद है। सत्ता पक्ष को भी भवित्व व लचीला रुख अपनाना चाहिए और विषय की मांगों के प्रति उदार रखेंगा रखना चाहिए। विषय की मांगों को खिजकर करने की प्रवृत्ति भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संसद जन प्रतिनिधि हैं, इस नाते वे सर्वेधार्मिक रूप से संसद के प्रति बंधे हुए हैं। संसद से लोकतंत्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। संसद सत्र विधेयक करने, राष्ट्रीय मुद्दों पर विषय करने, नया कानून बनाने आदि के लिए आहूत होते हैं, लेकिन इसे होंगा वा नरेबाजी का मच बना देने से इसकी उपयोगता व्यर्थ हो जाती है। 2014 से अब तक कांग्रेस ने शायद ही किसी संसद सत्र को मुचारू चलने दिया है। सरकार की अपील पर विषय को गैर करना चाहिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा है कि 'लोकतंत्र जनता की भलाई के लिए संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और बहस को कहा जाता है, इस पर भी विषय की मांगों के प्रति उदार रखेंगा रखना चाहिए।' अभी जबकि देश मणिपुर की लोकतंत्र घटना से आक्रोशित है, वहाँ हिंसा व उत्तरदाव की लेकर अफवाह व फज्जी खबरों या फेक वायरल वीडियो आदि से फिर से हिंसा भड़कने का खतरा विद्यमान है, तो ऐसे में इस संदर्भशील मुद्दों पर राजनीति करना कहीं उचित नहीं है। मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल की घटना भी शर्मनाक है। महिलाओं के उत्तीर्ण पर चाहे राजनीति भाजपा करे या कांग्रेस, दोनों गलत हैं। सियासत के लिए देश को नकारत, हिंसा आदि की आग में झोका निकृष्ट कर्त्त्य है। सबकी कोशश मणिपुर में व्याशीशी शांति बहाली की होनी चाहिए। सभी दल संसद चलने दें।

पृष्ठतिथि

कृष्ण प्रताप सिंह



जगन्नाथ आजाद का भी नहीं हुआ पाकिस्तान

वर्ष 1947 में देश के विभाजन के बाद अस्तित्व में एप एपाकिस्तान का पहला कोमीं तराना उस वक्त के उड़े के लाहौर निवासी बहद मकबूल हिन्दू शायर जगन्नाथ आजाद ने रखा था? अब इस बात को याद रखना पाकिस्तान को भी भी गवारा नहीं है। हालांकि, विभाजन के हिन्दू-मुस्लिम वैमन्स के दिनों में यह बहुत बड़ी बात थी कि जगन्नाथ आजाद ने पाक के लिए एप एपाकिस्तान को अद्वितीय बनाया रखा था। अब इस बात को याद रखना चाहिए और विषय की मांगों के प्रति उदार रखेंगा रखना चाहिए। विषय की मांगों को खिजकर करने की प्रवृत्ति भी लोकतंत्र के लिए लोगों की संख्या 2019-21 में 11.5 फीसदी हो गई है। यह सूचकांक आय गरीबी के आकलन की पूरी की व्यवधान के लिए लोगों का अनुपान है। इसके सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लिए लोगों का व्यवसाय द्वारा जारीपाई किया जाता है। इस पर विषय की हार पाया रखना है कि संसद में वह यह तभी ही पाया, जब संसद सुचारू रूप से चलेगी। संसद सत्र आहूत होने के बाद हर दिन करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, ऐसे में संसदों का दायित्व है कि वह संसद के संचालन में सहयोग करें, केवल पार्टी पार्लिमेंट के लिए संसद सत्र को बेकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि संसद के सुचारू व नियमित संचालन के लिए कुछ कठोर नियम बनाएं, जो लागे कि भारत की 21वीं सदी की संसद है। संसद से लोकतंत्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। संसद सत्र विधेयक करने, राष्ट्रीय मुद्दों पर विषय करने, नया कानून बनाने आदि के लिए आहूत होते हैं, लेकिन इसे होंगा वा नरेबाजी का मच बना देने से इसकी उपयोगता व्यर्थ हो जाती है। 2014 से अब तक कांग्रेस ने शायद ही किसी संसद सत्र को मुचारू चलने दिया है। सरकार की अपील पर विषय को गैर करना चाहिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा है कि 'लोकतंत्र जनता की भलाई के लिए संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और बहस को कहा जाता है, इस पर भी विषय की मांगों के प्रति उदार रखेंगा रखना चाहिए।' अभी जबकि देश मणिपुर की लोकतंत्र घटना से आक्रोशित है, वहाँ हिंसा व उत्तरदाव की लेकर अफवाह व फज्जी खबरों या फेक वायरल वीडियो आदि से फिर से हिंसा भड़कने का खतरा विद्यमान है, तो ऐसे में इस संदर्भशील मुद्दों पर राजनीति करना कहीं उचित नहीं है। मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल की घटना भी शर्मनाक है। महिलाओं के उत्तीर्ण पर चाहे राजनीति भाजपा करे या कांग्रेस, दोनों गलत हैं। सियासत के लिए देश को नकारत, हिंसा आदि की आग में झोका निकृष्ट कर्त्त्य है। सबकी कोशश मणिपुर में व्याशीशी शांति बहाली की होनी चाहिए। सभी दल संसद चलने दें।

अलका सिंह, योग विशेषज्ञ

योगासन केवल शारीरिक विकास के लिए ही नहीं होता है, बल्कि उनका मानसिक और आध्यात्मिक असर भी होता है। अगर हर तरह के योग करने के बाबत आजाद को अपना कोमीं तराना बनाना मानो। यह लगभग वैसी ही बात थी जैसे बंटवाय के बाबत के बेंद खारब हालात में लाहौर में जीना दूर्भाग्य हो जाए। अब उसके बाबत आजाद को अपना योगीपूर्ण पर यह याद करना चाहिए। विषय की मांगों के प्रति उदार र

